(7) मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के पयालीखंड-बेहरागढ़ीह-कोडोमाले क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश के मद्दुर किम्बरलाइट प्रांत में किम्बरलाइट शैल, जो हीरों का शैल है, का पता चला है।

(8) उड़ीसा में 20% कट आफ ग्रेड का 7.34 मिलियन टन मैग्नीज अयस्क और मध्य प्रदेश में मध्यम ग्रेड का 2.17 मिलियन टन मैग्नीज अयस्क।

(9) अनुमान है कि लिलांग घाटी, मेघालय में उच्च ग्रेड के 2265 मिलियन टन चूना-पत्थर भंडार हैं।

(10) तमिलनाडु में 3.38 मिलियन टन (0.05% से 0.116% एम ओ) मोलिब्डेनम अयस्क

(11) उमपार्था, मेघालय में सूचित किए गए आधारभूत खनिजीकरण का विस्तार।

(ग) खनिज गवेषण एक सतत् प्रक्रिया है और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष खनिज अन्वेषण का कार्य करता है।

(घ) खनिज नीति के उदारीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों/निजी क्षेत्रों को सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार खनिजों का गवेषण करने की अनुमति दी गई है।

Policy formulation for development of SSI units during the 9th Plan

1672. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to take policy decisions for the development of small scale industrial units in the country in the Ninth Plan;

(b) if so, the details thereof with the objectives;

(c) whether Government also propose to make a code of conduct for subcontracting, promotion of sub-contracting exchanges through systematic information on SSI capabilities etc.; and

(d) if so, the details thereof with other provisions to be made?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Necessary changes in policies and programmes for the development of Small Scale Industrial units in the country are a continuous process. The 9th Five Year Plan is yet to be finalised and clear picture will emerge only after the finalisation of the strategies in the 9th Plan.

(c) and (d) Sub-Group on Ancillary & Sub-contracting of the Working Group on Small Scale Industries for the Ninth Five Year Plan (1997-2002) has suggested on the need for developing a national Code of conduct for promoting sub-Contracting in the SSI Sector. No decision has, however, been taken on this as Ninth Plan is yet to be finalised.

भारत में विदेशी उपक्रमों द्वारा निवेश

1673. प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद कितने विदेशी उपक्रमों को भारत से निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है और रुपयों में कितनी राशि की अनुमति दी गई है;

(ख) इसमें से कितनी राशि का निवेश उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन हेतु किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इससे भारत के कुटीर और लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वर्तमान सरकार द्वारा 30.9.96 तक कुल 760 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं जिनमें 15167.77 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना है, अनुमोदित किया गया है।

उपर्युक्त अवधि के लिए अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के क्षेत्रीय-वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 179 अनुपत्र सं॰ 36] इसमें उपभोक्ता वस्तुओं सहित सभी क्षेत्रों के आंकड़े शामिल हैं।

(ग) लघु क्षेत्र के लिए 836 मदों के आरक्षण हेतु प्रावधान है। यदि कोई औद्योगिक इकाई लघु क्षेत्र में नहीं है और वह लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का

विनिर्माण करना चाहता है तो इसके लिए उसे अपने उत्पादन का 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व पूरा करना होता है।

Functioning of Trifed

1674. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT
RAMACHANDRA JICHKAR.

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED) has deviated from its essential function of marketing develop ment for tribals and lays more stress on felicitation functions for exporters and the like;

(b) the substantial achievements made by TRIFED in the area of marketing development for tribals;

(c) whether any review of TRIFEDs work has been done;

(d) if so, the finding thereof; and

(e) the steps proposed to be taken to improve the functioning of TRIFED?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) No Sir;

(b) The procurement by TRIFED has increased from Rs. 10.95 crores in 1988-89 to Rs.140.93 crores in 1995-96, Similarly sales have also increased from Rs. 9.26 crores to Rs. 115.15 crores over the same period. The intervention of TRIFED has helped to increase the price paid to tribals for their produce.

(c) The Ministry reviews the activities of TRIFED on the basis of monthly performance reports obtained from it.

(d) and (e) On the basis of reviews TRIFED has been asked to take measures to increase procurement of minor forest produce items, reduce carry over stock to the minimum increase direct procurement from tribals etc.

उपभोक्ताओं से सुपर बाजार के विरूद्ध विभिन्न प्रकार की शिकायतें

1675. श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार के विरूद्ध उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकार की शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है अथवा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिन प्रतिदिन इन शिकायतों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ग) उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर किये जाने के लिए क्या कारगर उपाय किये जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उसके मुख्यालय तथा क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों में समय-समय पर ग्राहकों से वस्तुओं की गुणवत्ता, स्टाक उपलब्ध न होने तथा कर्मचारियों से व्यवहार के बारे में शिकायतें प्राप्त होती है और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सभी शिकायतों पर वरिष्ट अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है और उन्हें दूर करने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जाते है।

Review of the functioning of the national institute of social defence

1676. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the functioning of the National Institute of Social Defence needs drastic review;

(b) if so, whether Government are contemplating any action in this regard;

(c) whether several social scientists have suggested several changes in the working of the Institute; and